

भाजपा की घबराहट या रणनीति

अहम है लाकत्र के लिए

इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना शुरू से विवादास्पद थी। जो अनुभव रहा, उससे इसके खिलाफ आरंभ ही कही गई बातें लगातार ठोस साबित होती गईं। इनके बीच यह तर्क महत्वपूर्ण था कि असीमित और गुप्त राजनीतिक चंदा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के तकाजे के खिलाफ है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय लोकत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा योगदान किया है। यह योजना शुरू से विवादास्पद थी। जो अनुभव रहा, उससे इसके खिलाफ आरंभ ही कही गई बातें लगातार ठोस साबित होती गईं। इनके बीच दो तर्क महत्वपूर्ण थे- पहला यह कि असीमित और गुप्त राजनीतिक चंदा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के तकाजे के खिलाफ है। दुसरी दलील यह थी कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना में शामिल प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मिले सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इन दोनों ही तर्कों को अब सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब ठहराया है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस निकर्षे पर पहुंचा कि गुप्त चंदे का प्रावधान सूचना के अधिकार के खिलाफ है। इस प्रावधान के तहत एक और आपत्तिजनक बात यह रही है कि चंदा देने वाली कंपनियों की पहचान आम जन से तो छिपी रहती है, लेकिन उपकरण को यह सब पाला जाता है कि तौर पर किसीको किसी चंदा देने

उनको लग रहा है कि कपूरी ग़ाकुर को मरणोपरात् भारत रह देकर भाजपा अंतिम समय में आति पिछड़ा गोट आधार का साधने की राजनीति कर रही है। ऐसे लोग घौंसी चरण सिंह को मरणोपरात् भारत रह से समानित करने और उनके पोरा जयंत घौंसी की एनडीए में वापसी को भाजपा का डेस्ट्रोट अंतेम मान रहे हैं। तमिलनाडु के रहने वाले महान् कृष्ण वैज्ञानिक व अर्थशास्त्री एमएस स्वामीनाथन और आंध्र प्रदेश के रहने वाले पूर्ण प्रथानमंत्री पीवी नरसिंह राव को मरणोपरात् भारत रह देने को दक्षिण भारत में पैर जमाने की कोरिश के तौर पर देख जा रहा है। एक सामान्य नैटवर्क राह बना है जिसमें नोटी ने कपूरी ग़ाकुर के जरिए नंडल का, लालकृष्ण आडवाणी के जरिए मटिर का, पीवी नरसिंह राव के जरिए मार्केट व और स्वामीनाथन व घौंसी चरण सिंह के जरिए मंडी को यानी किसानों को साधने का प्रयास किया है। यह सवाल भी पूछ जा रहा है कि जब अयोध्या में श्रीराम जन्मगमि मटिर का उद्घाटन हो गया और रामलला विराज गए और कारी व गमथुरा का अभियान शुरू हो गया तो भाजपा को क्या जयंत घौंसी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ज़खरत है? यह सवाल भी ही विस्तृत अगर बिहार में आति पिछड़ों के मसीहा रहे कपूरी ग़ाकुर को भारत रह दे दिया और वैर यादव पिछड़ा गोट भाजपा के साथ जाने तो किस उसे नीतीश की ज़खरत वर्तों है? जब अंजित पवार से तालमेल कर लिया तो मराठा गोट के लिए अशोक चलाण के वर्तों ज़खरत है?



अंगारा छूपडा
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

युनाव का लेकर आत्मविश्वास में हैं या घबराहट में हैं? यह एक ऐसे सवाल है, जिसके जवाब को लेकर इस समय देश भर में बहस हो रहा है। सोशल मीडिया ने ऐसी बहसों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मुहूर्या कराया है। पारंपरिक मीडिया में चलने वाले एकत्रफा चच्चाओं के बीच सोशल मीडिया में दोनों तरह के नैरेटिव वे लिए जगह बनी हैं। एक तरफ ऐसे मानने वाले लोग हैं कि प्रधानमंत्री अभी आत्मविश्वास में हैं इसलिए उन्होंने चार सौ पार का नारा दिया है। उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटें तो नहीं देगी और एनडीए को चार सौ वो पार पहुंचा देगी। अपने इस भाषण से पहले ही उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की बात शुरू कर दी थी और उसका एजेंडा तय करने लगे थे। यह विषय के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक रणनीति थी हो सकती है लेकिन उन्होंने ऐसा भरोसा दियाथा है, जिससे विषय का आत्मविश्वास निश्चित रूप से हिला

के नराटव के बाथ एक दूसरा पक्ष ह, जो भाजपा की ओर से किए जा रहे माइक्रो मैनेजमेंट के सक्ती घबराहट के तौर पर देख रहा है। अनेक लोग ऐसे हैं, जो नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कराने के राजनीतिक घटनाक्रम को भाजपा की घबराहट या बेचैनी के रूप में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देकर भाजपा अतिम समय में अति पिछड़ा वोट आधार को साधने की राजनीति कर रही है। ऐसे लोग चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने और उनके पोते जयंत चौधरी की एनडीए में वापसी को भाजपा का डेस्प्रेट अटेम्प मान रहे हैं। तामिलनाडु के रहने वाले महान कृषि वैज्ञानिक व अर्थशास्त्री एमएस स्वामीनाथन और आंध्र प्रदेश के रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पीली नरसिंह राव को मरणोपरांत भारत रत्न देने को दक्षिण भारत में पैर जमाने की कोशिश के तौर पर देख जा रहा है। एक सामान्य नैटिव यह बना है कि मोदी ने कपूरी जाइवाणा के जारी मादाका, पावन नरसिंह राव के जरिए मार्केट को और स्वामीनाथन के चौधरी चरण सिंह के जरिए मंडी को यानी किसानों को साधने का प्रयास किया है। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हो गया और रामलला विराज गए और काशी व मथुरा का अभियान शुरू हो गया तो भाजपा को क्यों जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की जुरुरत है? यह सवाल भी है कि अगर बिहार में अति पिछड़ों के मसीहा रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया और गैरी यादव पिछड़ा वोट भाजपा के साथ है तो फिर उसे नीतीश की जसरत क्यों है? जब अजित पवार से तालमेल का लिया तो मराठा वोट के लिए अशोक चक्रवाहन की क्यों जसरत है? देश भर में विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाइयां या उनको तोड़ कर भाजपा में शामिल कराने या कर्नाटक से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश पर्याप्त जाब और महाराष्ट्र तक के नए

जा रहा है कि भाजपा में घबराहट और वह अंतिम समय में इस तरफ के उपाय कर रही है, जो कानूनी भी हो सकते हैं। विकसित संकल्प यात्रा, अमृत काल में विकसित बनार्न, भारत के विद्युत गूरु बनने, मोदी के मजबूत नेतृत्व विषय के खट्ट होने पर चरार, रामगढ़ के उद्घाटन, अनुच्छेद 370 की समाज और समाज नागरिक संहिता के बाबत भाजपा जिस तरह के छोटे छोटे प्रयत्न कर रही है उसको उसकी घबराहट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या इसके माइक्रो मैनेजमेंट को घबराहट जाना चाहिए या इसे पार्टी की रणनीति मान कर इसका विशेषण होना चाहिए? सोचें, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए लिए चार सौ सीट का लक्ष्य घोषित कर दिया है तो क्या वह उसी लक्ष्य का चानव लड़ कर हासिल हो जाएगा? जैसे पिछला चुनाव लड़ा गया था? लक्ष्य को हासिल करने के लिए

बनाना हाता है और वह काम सारा पार्टीयां करती हैं। आखिर लगातार दो चुनावों में बुरी तरह से हारने के बाद ही तो राहुल गांधी को ख्याल आया कि पुरे देश की यात्रा करते हैं। सक्रिय राजनीति में आने के 18 साल के बाद राहुल सितंबर 2022 में पदवयात्रा पर निकले थे। लगातार दो चुनाव हारने के बाद ही विपक्षी पार्टीयोंने साथ मिल कर भाजपा से मुकाबला करने का फैसला किया था। पिछले साल मई-जून में विपक्षी पार्टीयोंने भाजपा की नींद उड़ाई थी, जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती और उसके बाद 26 पार्टीयोंने एकजुट होकर फैसला किया कि भाजपा के हर उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारेंगे। उसके बाद ही भाजपा को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ी है। सो, यह सवाल बचकाना है कि जब राममंदिर हो गया या जब ये सारे काम हो गए तो इतने माइक्रो मैनजमेंट की क्या जरूरत है। इस तरह के सवाल हर बार पूछे जाते भ्रष्टाचार मादा अधायुव न समझ कर रहे होते हैं या एक राज्य कई कई बार रैलियां करते हैं। लेकिन किसी भी मुकाबले का कोरे सिद्धांत यह है कि जब लड़ें तो पूरी तैयारी अन्त तकत के साथ लड़ें। आधी अधुरे लड़ाई का कई मतलब नहीं होता है। अगर किसी के पास संसाधन हैं तो तकत है तो उन्हें लड़ाई में झोंका होता है। उसे बचा कर रखने का कर्तव्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इसिद्धांत से चुनाव में उत्तरते हैं। वे कैसर नहीं छोड़ते हैं। जंग जीतने वाले साम, दम, दंड और भेद सबका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नेंद्र मोदी की चुनावी राजनीति को निकट अर्ती के झितास से समझने की जरूरत है। वे कोई भी चीज संयोग के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। अपनी तरफ से सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इसमें कई बार विफलता भी मिल हो लेकिन इससे हर लड़ाई में अपने सब कुछ झोंकने की उनकी सोच न बदलती है।

सोनिया गांधी के इस फैसले को लेकर सियासी उत्तापटक शुरू हो गई है। भाजपा ने सोनिया गांधी पर जहाँ तंज कसा है। वहीं कांग्रेस ने सोनिया गांधी के फैसले को पार्टी का अपना फैसला बताया है। कांग्रेस बेहद बुरे दौर से गज़र रही है। बढ़िया गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी ने पार्टी को संभाला। राजीव की अनपरिश्ठित में

सानिया गावा न अपना भूमका बखूबा। नमीइ लाकन राहुल गावा खर उत्तरत नहा। दाख रह ह। दाक्षण्यवद् विचारधारा की पोषक भारतीय जनता पार्टी में मोदी युग की शुरुवात के बाद कांग्रेस का विश्वास जनता में सिकुड़ता गया है। कमजोर कांग्रेस को मजबूत आधार दिलाने वाला कोई राजनेता नहीं दिख रहा है। प्रियंक गांधी से पार्टी समर्थकों से काफी उम्मीद थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव में उन्हें जो करिश्मा करना था वह नहीं कर पाई। ऐसी ऐसी स्थिति में सक्रिय राजनीति से सोनिया गांधी का अलविदा कहना कांग्रेस को किस दिशा में लेकर जाएगा यह कहना मुश्किल है। कांग्रेस आज भले कमजोर हो गई है, लेकिन कांग्रेस से अधिक लोगों को गांधी परिवार पर सबसे अधिक भरोसा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की रायबरेली परंपरागत सीट रही है। रायबरेली और अमेठी का नाम आते ही लोगों के सामने गांधी और नेहरू परिवार की तस्वीर तैरने लगती है। लेकिन कमजोर होती कांग्रेस ने अपनी बहु चर्चित लोकसभा सीट अमेठी को गंवा दिया।



देख संभालने के लिए उन्हें अंतर राजनीति सोनिया गांधी
नहीं में आना पड़ा। लेकिन सोनिया गांधी निभाइ। ले
की लगता है अब सक्रिय राजनीति को उतरते नहीं

राजीव गांधी का खोने के बाद कहा था। वह एक माँ और औरत की पीड़ियाँ थीं। क्योंकि राजीव गांधी को खोने वेंटे बाद सोनिया गांधी अकेली पड़ गयी थीं। वह डरी और सहमी थी क्योंकि पारिवारिक संघर्ष में वह अकेली थीं उन्हें सबसे अधिक फिक्र दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका गांधी के सुरक्षा की थी। जिसकी वजह से वह राजनीति में नहीं आना चाहती थीं। क्योंकि राजनीति की वजह से उन्होंने पति और सास को खोया था। जिसकी वजह से उन्हें राजनीति से बूछा हो गई थी। गांधी परिवार के लिए दोनों घटनाएँ बेहद दुःखद थीं। लेकिन सोनिया गांधी का दृष्ट संकल्प उन्हें विषम परिस्थितियाँ में भी डिगने नहीं दिया। कांग्रेस के

क्या

के चलते अब वह चुनाव नहीं लड़ागा और राज्यसभा के माध्यम से कांग्रेस की सेवा करेंगी। उन्होंने रायबरेली की जनता के नाम एक भावनात्म चिठ्ठी भी लिखी है। सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद रायबरेली की सीट क्या कांग्रेस के लिए सुरक्षित रह पाएगी या अपेंटी की तरह उस पर भी भजपा का कब्जा हो जाएगा। सोनिया गांधी के इस फैसले को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो गई है। भाजपा ने सोनिया गांधी पर जहाँ तंज करा है। वर्ही कांग्रेस ने सोनिया गांधी के फैसले को पार्टी का अपना फैसला बताया है। कांग्रेस बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी ने पार्टी को संभाला। राजीव की अनुपस्थिति में पाटा में मादा युग का शुरुवात के बावजूद कांग्रेस का विश्वास जनता में सिकुड़त हो गया है। कमज़ोर कांग्रेस को मजबूती आधार दिलाने वाला कोई राजनेता नहीं दिख रहा है। प्रियंका गांधी से पार्टी समर्थकों से काफी उम्मीद थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव में उन्हें जो करिशमा करना था वह नहीं कर पाई। ऐसी ऐसी स्थिति में संक्रिया राजनीति से सोनिया गांधी का अलविदा कहना कांग्रेस को किस दिशा में लेकर जाएगा यह कहना मुश्किल है। कांग्रेस आज भले कमज़ोर हो गई है, लेकिन कांग्रेस से अधिक लोगों को गांधी परिवार पर सबसे अधिक भरोसा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की रायबरेली परंपरागत

सचनुप्रकृदिता की

कांग्रेस ने अपना बहु चांचत लाकसभा सीट अमेठी को गंवा दिया। राहुल गांधी को विषम राजनीतिक परिस्थितियों में नई सियासी जमीन तलाशने के लिए दक्षिण भारत से चुनाव लड़ना पड़ा। अब यह निश्चित हो गया है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के माध्यम से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगी। फिर सबाल उठता है क्या रायबरेली सीट कांग्रेस से हाथ से फिसल जाएगी। जबकि सोनिया गांधी स्वयं वहाँ से सांसद हैं। कांग्रेस के जो राजनीतिक हालात हैं उस स्थिति में राहुल गांधी क्या अमेठी एवं रायबरेली लौटेंगे। गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट रायबरेली का फिर क्या होगा। क्या गांधी परिवार से उपेक्षित होने के बाद यह सीट गांधी या राहुल गांधी का रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि यह खबर भी आयी है की प्रियंका गांधी अमेठी और राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी क्या वायनाड को छोड़कर रायबरेली से अपना चुनावी भविष्य तय करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जबकि दक्षिण भारत में भाजपा अभी कमजोर स्थिति में है। उसे हालत में राहुल गांधी अगर वायनाड को बाय-बाय कर रायबरेली से अपना भाग्य आजमाते हैं तो दक्षिण के लिए गलत संदेश जाएगा और दक्षिण में कांग्रेस कमजोर होगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय खराब स्वास्थ्य और बढ़ता उम्र व हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि हालांकि मुझे आपकी सीधे सेवा करना का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन मन और प्राण से आपके साथ रहने वायबरेली की जनता के नाम सोनीया ने एक बहुत ही भावनात्मक लाइलिखी हैं मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवर्को को वैसे संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। उन्होंने आगे अपना बात में लिखा है कि दिल्ली में मेरे परिवार अधूरा है वह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूछ होता है। चिट्ठी में ससुर फिरोज गांधी और सास इंदिरा गांधी का भी जिम्मा किया है।

अब दंश का सबसे बड़ा अदालत का करावा माना जाता है। शुरूआत में ऐसा लगा कि ये घटना सिर्फ एक हमले तक ही सीमित है, लेकिन शेष के फरार होते ही इलाके की महिलाएं अचानक बाहर चलने लगीं। पहिला तो आया था, उसके बाद दूसरा भी आया था। यह दोनों घटनाएं जारी रहीं। यह दोनों घटनाएं अनेक अवधारणाओं का उत्पन्न हुए।

ममता बनजा के राज में भाजपा तो हल्कान है ही

ममता बन्जारा का मप्र कहा जान वाले कांग्रेस भी परेशान है। बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुश्री ममता बनर्जी को कूरता की रानी तक कहा दिया है। लेकिन व्या सचमुच ममता बनर्जी कूरता की रानी हैं या उन्हें कूरता का प्रतीक बनाने की कोशिश की जा रही है। ताजा मामला सदैशखली में महिलाओं के उत्पीड़न का है। बंगाल में आठ दशक बाद भी साम्प्रदायिक जहां समाप्त नहीं हुआ ह। बंगाल नोआखर्ला से चलकर सदैशखली तक हिंसा में है।

उससे कराब 80 किलोमीटर दूर स्थित संदेशखाली। संदेशखाली उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखण्ड में आता है। ये बांगलादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। इस इलाके में अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। संदेशखाली उस वर्क सुर्खियों में आया, जब तृण मूळ कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। आरोप है कि शेख और उनके समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया। आरोपी फरार है। शाहजहां को

ल अड़ा। माहलाओं न शाहजहां
और उनके समर्थकों पर अत्याचार
करते थे, यौन उत्तीर्ण करने और जमीन-
पानाने जैसे गंभीर आरोप लगा डाले
ताओं का आरोप है कि तृमूकां के
गांव में घर-घर जाकर चक्र करते
और इस दौरान अगर घर में कोइ
महिला या लड़की दिखती है तो
सभी नेता शाहजहां शेख के लिए
अगवा कर ले जाते थे और फिर
पूरी रात अपने साथ पार्टी दफ्तर
अन्य जगह पर रखा जाता था।
दो दिन यौन उत्तीर्ण करने के बाद
उसके घर या घर के सामने छोड़

राजनीति भा जम कर का जा रहा ह। सबसे पहले भाजपा ने संदेशखाली के मामले को लेकर राजनीति की। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने संदेशखाली जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे रास्ते में ही रोदिय। इसके बाद तृण मूल कांग्रेस से नाराज बैठी कांग्रेस भी मैदान में आ गयी। कांग्रेस सांसद और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को संदेशखाली में तनाव की स्थिति में जाने से रोका गया है। पुलिस और अधीर रंजन चौधरी के बीच नोकझोक हुई है। नरेबाजी करते कांग्रेस नेता और कांग्रेस प्रतिनिधि जब आगे बढ़ रहे थे, पुलिस लिए कांग्रेस के माल्लका जुनिहुड़ग का नाम प्रस्तावित किया, इसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू गठबंधन से बाहर हो गयी। बाद में ममता ने बंगाल में कांग्रेस को अपेक्षित सीटें न देकर रार बढ़ा। कांग्रेस और ममता के रिश्ते तब और बिंगड़े जब राहुल गांधी की भारत जोड़े न्याय यात्रा के साथ भी ममता सरकार ने बदलसलकी की। अब संदेशखाली के लिए आई बढ़ने से कांग्रेस सांसद ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, ममता क्रूरता की रानी है वह आग से खेल रही है। अधीर रंजन ने कहा कि हम सब कुछ राजनीतिक तौर

17 वर्ष बाद भी तरैया में नहीं बना बीआरसी भवन

प्रातःकिरण संवाददाता



चलता है शिक्षकों के कार्य को लेकर बीआरसी में आज जाने के चलते उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्यकारी भवन का निर्माण 17 वर्ष बाद भी नहीं हो सका है बीआरसी भवन का निर्माण वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। भवन के निर्माण कार्य शुरू होकर लिटर तक बन कर रह गया बीआरसी भवन के निर्माण कार्य विधायक तथा शिक्षण संबंधित कार्य के लिए किया जा रहा है जिसे के लिए गाड़ी बाहर से आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं। इसके बाद भवन के निर्माण कार्य विधायक तथा शिक्षण संबंधित कार्य के लिए गाड़ी बाहर से आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं।



वाचन के लिए अद्यार्थ धर्म पूर्णपूर्वक उपलब्ध होने के बाद भवन का निर्माण अधिकारी अमन समीर ने जिसे में सरकार और योग्यांशों को लेकर जिला टारक फोर्म (डीटीए) की समीक्षा करते हुए कहा कि टीवी मुक्त अधियान को शत प्रतिशत पूरा करना होगा। इसके लिए पंचायत सरकार द्वारा टीवी मरीजों की पहचान और संदिग्ध रोपियों की जांच को बढ़ावा दी गई। जिलाधिकारी और मध्येत्री और मध्येत्री के रोपियों की विशेष रूप से जांच कराने की जिम्मेदारी विधायक की होगी। जिलाधिकारी अमन समीर ने समीक्षात्मक बैठक के द्वारा उपरिक्षेत्र में जिसके बाद भवन के निर्माण कार्य और कर्मी के पांच बालों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं।

